भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3454

दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओडीओपी निर्यात में वृद्धि

3454. श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) उत्पादों के कुल मूल्य और मात्रा का आन्ध्र प्रदेश के एलुरु सहित राज्यवार/जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत भर में ओडीओपी उत्पादों के लिए निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारत से ओडीओपी के निर्यात को बढ़ाने के लिए आवश्यक अवसंरचना के विकास और उन्नयन में निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों को आंमत्रित करने का विचार किया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने ओडीओपी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई प्रशिक्षण/कौशल विकास पहल/योजना/स्कीम चलाई है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश विशेषकर एलुरु जिले में ऐसी पहल/योजना/स्कीमों के अंतर्गत चलाए गए कार्यक्रमों की सूची क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) आंध्र प्रदेश (एलुरु जिले सहित) के जिला–वार ओडीओपी उत्पाद निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://static.investindia.gov.in/s3fs-public/2024-11/odop_product_list_november_0.pdf

मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी भी डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के सहयोग से निर्यात संवेदीकरण और संवर्धन कार्यशालाओं के आयोजन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों के साथ कार्य कर रहा है। ये कार्यशालाएँ हितधारकों को वैश्विक व्यापार को संचालित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये कार्यशालाएँ सभी हितधारकों को सशक्त बनाकर, उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो भारत के व्यापक निर्यात वृद्धि उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है।

इसके अलावा, ओडीओपी और निर्यात हब के रूप में जिले (डीईएच) पहल के तहत पहचाने गए उत्पादों और सेवाओं की दृश्यता को बढ़ावा देने और इसमें वृद्धि करने के लिए भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयासों में, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ जुड़ाव, आभासी क्रेता–विक्रेता बैठकें और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में आयोजित जी–20 बैठकों के दौरान उपहार के रूप में कई ऐसे उत्पादों को शामिल किया गया, जिससे इन उत्पादों की वैश्विक प्रोफ़ाइल को बढ़ाने में और योगदान मिला है।

(घ) निर्यात हब के रूप में जिले पहल के तहत देश के सभी जिलों में निर्यात के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने और निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, और जिलों के साथ–साथ डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रमुख ई–कॉमर्स भागीदारों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र सरकार के हितधारकों, उद्योग संघों आदि के साथ आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ताकि भाग लेने वाले व्यवसायों के साथ–साथ छोटे पैमाने के निर्यातकों और एमएसएमई के लिए बहुमूल्य सहायता, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सत्र प्रदान किए जा सकें, जिससे उन्हें वैश्विक बाजारों में सफल होने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और सहायता मिल सके। डीजीएफटी ने एक्ज़िम बैंक के एक्जिम ग्रिड कार्यक्रम (विकास के लिए जमीनी स्तर की पहल) के माध्यम से डीईएच–ओडीओपी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्ज़िम बैंक के साथ भी भागीदारी की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र–विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना और सहायता हेतु उपयुक्त लाभार्थियों की पहचान करना है। आंध्र प्रदेश सहित राज्यों में ओडीओपी उत्पाद के निर्यात संवर्धन हेतु आयोजित कुछ कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. ओडीओपी पहल के अन्तर्गत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) के सहयोग से, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डिजाइन संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी कुल 29 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
2. ओडीओपी पहल के तहत (राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम) जैविक प्रमाण अभियानों को चलाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्य किए जा रहे हैं। ये अभियान किसानों को जैविक प्रमाणीकरण पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और पात्र किसानों के लिए प्रमाणीकरण की सुविधा में सहायता करते हैं। 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 18 एनपीओपी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जो विभिन्न ओडीओपी उत्पादों के लिए जैविक खेती को औपचारिक मान्यता दिलाने में योगदान दे रही हैं।
3. निर्यात हब के रूप में जिले पहल के तहत आयोजित आउटरीच कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में आंध्र प्रदेश के जिलों में 700 से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी के साथ हाल ही में पांच निर्यात जागरूकता बैठकें/हितधारक बैठकें आयोजित की गई हैं।

*****